भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 246

बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>महाराष्ट्र में नये सौर पार्क</u>

246. डॉ. नामदेव किरसानः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर महाराष्ट्र में नए सौर पार्कों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र के गड़चिरोली में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) जी, हाँ। दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, सरकार ने "सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" के लिए योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित 13 राज्यों में 55 सौर पार्कों को स्वीकृति दी है। सौर पार्कों का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) गड़चिरोली, महाराष्ट्र में सौर विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) वर्तमान समय-सीमा के अनुसार, महाराष्ट्र में सौर पार्कों का निर्माण वर्ष 2025-26 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है।

(घ) सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। किए गए प्रमुख उपायों का ब्यौरा अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

<u>अनुलग्नक-I</u>

'महाराष्ट्र में नए सौर पार्क' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 246 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

<u>'सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास' के लिए योजना के अंतर्गत स्वीकृत सौर पार्कों की सूची (दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार)</u>

क्र.सं.	राज्य	पार्क का नाम	स्वीकृत क्षमता (मेगावाट)
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुरमु सौर पार्क	1400
2.		कुरनूल सौर पार्क	1000
3.		कडप्पा सौर पार्क	1000
4.		अनंतपुरमु-II सौर पार्क	500
5.		रामगिरी सौर पार्क	300
6.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव सौर पार्क	100
7.	गुजरात	राधनेसदा सौर पार्क	700
8.		धोलेरा सौर पार्क	1000
9.		एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा पार्क	4750
10.		जीएसईसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क	3325
11.		जीआईपीसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क चरण-I	600
12.		जीआईपीसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क चरण-II	1200
13.		जीआईपीसीएल अक्षय ऊर्जा पार्क चरण-III	575
14.	हिमाचल प्रदेश	पेखुबेला सौर पार्क	53
15.	झारखंड	सेकी फ्लोटिंग सौर पार्क	100
16.		डीवीसी फ्लोटिंग सौर पार्क चरण-I	755
17.		डीवीसी फ्लोटिंग सौर पार्क चरण-II	234
18.	कर्नाटक	पावागडा सौर पार्क	2000
19.		बीदर सौर पार्क	500
20.	केरल	कासरगोड सौर पार्क	105
21.		फ्लोटिंग सौर पार्क	50
22.		कासरगोड सौर पार्क चरण-II	100
23.	मध्य प्रदेश	रीवा सौर पार्क	750
24.		मंदसौर सौर पार्क	250
25.		नीमच सौर पार्क	500
26.		आगर सौर पार्क	550
27.		शाजापुर सौर पार्क	450
28.		ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क	600
29.		बरेठी सौर पार्क	630
30.		मुरैना पार्क	600
31.	महाराष्ट्र	साईं गुरु सौर पार्क	500

क्र.सं.	राज्य	पार्क का नाम	स्वीकृत क्षमता (मेगावाट)
32.		दोंडैचा सौर पार्क	250
33.		पटोदा सौर पार्क	250
34.		एराई फ्लोटिंग सौर पार्क	105
35.	मिजोरम	वंकल सौर पार्क	20
36.	ओडिशा	एनएचपीसी द्वारा सौर पार्क	40
37.	राजस्थान	भाडला-II सौर पार्क	680
38.		भाडला-III सौर पार्क	1000
39.		भाडला-IV सौर पार्क	500
40.		फलोदी-पोखरण सौर पार्क	750
41.		फतेहगढ़ फेज-1बी सौर पार्क	421
42.		नोख सौर पार्क	925
43.		पुगल सौर पार्क चरण-I	1000
44.		पुगल सौर पार्क चरण-II	1000
45.		आरवीयूएन सौर पार्क	2000
46.		ट्रेडको सौर पार्क	2000
47.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में सौर पार्क	365
48.		जालौन सौर पार्क	1200
49.		मिर्जापुर सौर पार्क	100
50.		कलपी सौर पार्क	65
51.		ललितपुर सौर पार्क	600
52.		झांसी सौर पार्क	600
53.		चित्रकूट सौर पार्क	800
54.		कानपुर देहात पार्क	75
55.		कानपुर नगर पार्क	35
कुल			39958

<u>अनुलग्नक-II</u>

'महाराष्ट्र में नए सौर पार्क' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 246 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

<u>देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रमुख उपाय</u>

- वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट/वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत बोलियों के लिए ट्रैजेक्ट्री की अधिसूचना।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास सेल स्थापित की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आदि जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।

- समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ (यूआरईटी) की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित समान प्रकार की व्यक्तिगत आरई परियोजनाओं के टैरिफ का औसत निकालकर उपभोक्ताओं को एक समान टैरिफ उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक 15 फरवरी, 2024 से "सौर विद्युत सेंट्रल पूल" और "सौर-पवन हाइब्रिड सेंट्रल पूल" के लिए यूआरईटी के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" की अधिसूचना जारी की गई है।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****